



स्पॉटलाइटगी इन्फ्रास्ट्रक्चर नविश

यह एडटोरियल 19/11/2022 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "The Infrastructure Imperative" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के अवसंरचना क्षेत्र को सशक्त करने से संबद्ध प्रमुख चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिये जा सकने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

आधारभूत संरचना या अवसंरचना क्षेत्र (Infrastructure sector) भारतीय अरथव्यवस्था के लिये एक प्रमुख चालक है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को आरंभ ले जाने के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और सरकार द्वारा इस पर गहन ध्यान दिया जाता है। देश भर में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर कई पहल की गई हैं।

- लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, अत्यधिक आधारभूत संरचना निर्माण के मार्ग में अभी भी कई बाधाएँ हैं। सतत उच्च विकास और एक प्रतिसिप्रदाधी विनिर्माण क्षेत्र की ओर भारत की राह सुडूँ और विश्वसनीय राष्ट्रीय आधारभूत ढाँचे से होकर ही गुज़री।

भारत में अवसंरचना का वर्तमान परिवर्त्य

- 'इंफ्रा-डेफिट इंडिया': भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा (ब्राजील के बाद) अवसंरचनागत घाटा रखने वाला देश है क्योंकि इसने 1990 के दशक की शुरुआत से ही 6% से अधिक की तीव्र गति से विकास किया है लेकिन आपूर्ति में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।
 - विश्व बैंक की '[भारत की शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्तपोषण](#)' ([Financing India's Urban Infrastructure Needs](#)) [शीर्षक रपोर्ट](#) के अनुसार, वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरी क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या के 40% भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।
 - इससे भारतीय शहरों की पहले से ही तनी हुई शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
 - वर्तमान में भारतीय शहरों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का महज 5% ही नजीब स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- अवसंरचना क्षेत्र का महत्व:
 - अवसंरचना क्षेत्र भारत के आरथिक विकास के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कारबा है क्योंकि यह टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण विकास परियोजनाओं जैसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास को संचालित करता है।
 - वैश्वक नविशकों ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिये भारत को अपने शीर्ष गंतव्य स्थलों में से एक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। भारत अपने युवा उभार, मध्यम वर्ग के उदय और वाशिल घरेलू बाज़ार के दम पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर उच्च प्रतिफ़िल या रटिरन दर की की पेशकश करता है।
- संबंधित पहलें:
 - सरकार ने वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के लिये अवसंरचना विकास को समर्थन देने हेतु [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन](#) (NIP) शुरू की है, जहाँ शहरी अवसंरचना प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।
 - सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समन्वय योजना और निषिद्धान के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना भी शुरू की है।
 - [राष्ट्रीय निविश और अवसंरचना कोष](#) (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) एक सरकार समर्थित इकाई है, जो देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूँजी प्रदान करने के लिये स्थापित की गई है। इसे दिसंबर 2015 में शरणी-II वैकल्पिक निविश कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
 - नवंबर 2021 में [भारत, इजराइल, अमेरिका और यूरोप](#) (I2U2) ने क्षेत्र में अवसंरचना विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिये एक नया चतुर्भुज आरथिक मंच स्थापित किया।
 - मार्च 2021 में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को निधि दिने के लिये [राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक](#) (National Bank for Financing Infrastructure and Development- NaBFID) की स्थापना के लिये संसद में इस आशय का एक विधियक पारिति किया गया।

संबंधित चुनौतियाँ

- भारत की सबसे बड़ी चुनौती वशिल अवसंरचनागत वित्तीय अंतराल है, जिसके जीडीपी के 5% से अधिक होने का अनुमान है।
- भूमि अधिग्रहण, आकर्षणक बोली लगाना और गैर-निषिपादति परसिंपत्तयों अवसंरचनात्मक PPPs (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के लिये प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- भारत तनावग्रस्त परसिंपत्तयों के उच्च स्तर का सामना कर रह है और अरथव्यवस्था के भविष्य के विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये ऋण वृद्धि को आधार के रूप में बहाल करने की आवश्यकता है।
 - बैंकों में तनावग्रस्त परसिंपत्तयों के साथ-साथ बैंकों की छोटी पूँजी के कारण इन परसिंपत्तयों पर अतरिक्त और संभावित रूप से गंभीर क्षति की स्थितिबन सकती है।
- इसके अलावा, करेडिट ब्याज दरों की स्थिरता की कमी से क्षेत्र में नविश के लिये एक उल्लेखनीय जोखमि उत्पन्न हुआ है।
 - यह तथ्य कि भारत में अवसंरचना नविश आम तौर पर USD पर अपेक्षित प्रतफिल/रटिरन पर आधारित होता है न कि उपयोगकरता शुल्क पर, एक असंतुलन का सृजन करता है और देश में विदेशी अवसंरचना नविश के कुल प्रवाह को प्रभावित करता है।

Roadblocks in key sectors



HIGHWAYS

- Delays in land acquisition; lenders stop lending midway
- Tendering of projects to low-traffic entity
- Unclear exit policy for road developer; NHAI is a developer as well as the regulator which causes a conflict of interest in case of arbitration so there is a need for a clear distinction of roles for NHAI

PORTS

- Multiple changes in tariffs setup by the Tariff Authority for Major Ports make it difficult to evaluate the cost of projects
- Delays in tariff fixation

AIRPORTS

- Lack of consistency in tariff methodology and concession tariff framework
- Switching from single till tariff method to hybrid till creates difficulty in assessing the cost of projects
- Delays in the passage of tariff orders cause problems in the timely execution of projects

WIND

- Inconsistent policy at Central and State govt level
- Accelerated depreciation leads to non-viability
- State regulators do not honour renewable purchase obligation

TELECOM

- Lack of predictability
- Inconsistent policy and regulatory framework; govt refuses to honour PPAs signed earlier
- Aggressive bidding to some extent

POWER

- Coal block deallocation causing execution delays and losses to project developers
- New auction-based coal linkage approved by government in 2017, uncertainty remains regarding the validity of old contracts
- Inconsistency in the interpretation of PPA
- Inconsistency in Central & State regulation, for instance, the Central electricity Act allows open access, but State governments do not adhere to it causing the problem in execution
- Unstable financial health of State utility causes a delay in the payment cycle

GREENFIELD PROJECTS

- Land acquisition delay
- Nature of developers have been contractors which leads to low-cost bidding making the project unviable
- Bank loans are given out for 10/15/18 years but the interest reset clause poses a high risk on overall investment return evaluation, sometimes 8% interest rates are increased up to 14-15% rendering the project unviable

BROWNFIELD PROJECTS

- Government questions the validity of existing projects (eg, with rates of solar energy slashing, will the contracts entered on higher tariffs remain valid or not?)

- There is a strong need for the ability to have more credible infrastructure developers and partners

UNIFIED LOGISTICS INTERFACE PLATFORM (ULIP) IS DESIGNED TO ENHANCE EFFICIENCY AND REDUCE THE COST OF LOGISTICS BY CREATING A TRANSPARENT, ONE-WINDOW PLATFORM

अवसंरचना क्षेत्र को सशक्त करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **नीतिनियमक ढाँचे में नरितरता सुनिश्चिति करना:** नविदि प्रकरण में एक बेहतर नियमक वातावरण और नरितरता की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में नरितरता और नीतिगत सामंजस्य की कमी को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहयि।
 - तनावग्रस्त परसिंपत्तयों की समस्या से निपटने के लिये सरकार और RBI के मध्य एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहयि। गैर-निषिपादति

संपत्तियों, PSUs के पुनरुद्धार के लिये सभी क्षेत्रों में एक समर्पित नीतिका नरिमाण करने की आवश्यकता है।

- **उचिति उपयोगकरता शुल्क:** अवसंरचन वित्तीयोषण, अवसंरचना सेवा प्रदाताओं की वित्तीय व्यवहार्यता और पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग संवहनीयता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है।
 - उपयोगकरता शुल्क महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर के कई क्षेत्रों में आंशकि रूप से शून्य या बहुत कम उपयोगकरता शुल्क के कारण कीमती संसाधनों (जैसे भूजल) का अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय होता है।
 - उचिति उपयोगकरता मूल्यों से प्रेरित पर्यावरणीय संवहनीयता एवं संसाधन उपयोग दक्षता के अलावा इस नीति प्राथमिकता में अपार संसाधन सृजन क्षमता भी है।
- **अवसंरचना का स्वायत्त वनियमन:** चूँकि भारत और विश्व नजी भागीदारी के लिये अधिकाधिक क्षेत्रों को खोल रहे हैं, नजी क्षेत्र अनविवार्य रूप से स्वायत्त अवसंरचना वनियमन की मांग करेगा।
 - विश्वव्यापी प्रवृत्तिबहु-क्षेत्रीय नियमकों की ओर है क्योंकि आधारभूत संरचना क्षेत्रों में नियमक भूमिका आम है और ऐसे संस्थान नियमक क्षमता का नरिमाण करते हैं, संसाधनों का संरक्षण करते हैं और नियमक कब्जे को रोकते हैं।
- **संपत्ति पुनर्चक्रण (AR) और BAM:** BAM (Brownfield Asset Monetisation) का मूल विचार ब्राउनफील्ड AR के माध्यम से अवसंरचनागत संसाधनों को बढ़ाना है ताकि डी-रसिक्ड ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में बंधी धनराशिको मुक्त करके त्वरित ग्रीनफील्ड नविश करिया जा सके।
 - इन परसिंपत्तियों को एक टरस्ट (InvITs) या एक कॉर्पोरेट संरचना (TOT मॉडल) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कैपिटल कंसिडरेशन (जो इन अंतर्निहित परसिंपत्तियों से भविष्य के नकदी प्रवाह के मूल्य पर कब्जा करता है) के बजाय संस्थागत नविशकों से नविश प्राप्त करता है।
 - भारत के पास अवसंरचना क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड संपत्तियों का एक बड़ा भंडार है।
- **घरेलू फंड का उपयोग:** भारतीय पेंशन फंड जैसे घरेलू स्रोत जो नियक्रिया पड़े हुए हैं, यदकि कुशलता से उपयोग किया जाएँ तो इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।
 - भारत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिये घरेलू धन के कुशल उपयोग पर कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं ऐसे अन्य देशों के अभ्यासों का अनुकरण कर सकता है।
- **वैश्वकि नेतृत्व का लाभ उठाना:** भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। विभिन्न G20 देशों ने अपनी अध्यक्षता में अवसंरचना के लिये एजेंडा नियमित किया है, जैसे किपरसिंपत्तिवर्ग के रूप में अवसंरचना के लिये रोडमैप (अर्जेंटीना, 2018), गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना नविश के सदिधांत (जापान, 2019), इंफ्राटेक (सऊदी अरब, 2020) और प्रतफिल/रकिवरी के लिये संवहनीय अवसंरचना का वित्तीयोषण (इटली, 2021)।
 - G20 की अध्यक्षता भारत के लिये एक अवसर है किंतु स्वयं के लिये और विश्व के लिये अवसंरचना एजेंडे को नियमित करे।

अभ्यास प्रश्न: “वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अवसंरचना विकास समय की आवश्यकता है।” टपिपणी कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न:

Q 1. 'राष्ट्रीय नविश और बुनियादी अवसंरचना कोष' के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2017)

1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
2. वर्तमान में इसके पास ₹4,00,000 करोड़ का कोष है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

Q 2. भारत में "सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है (वर्ष 2020)

- (A) डिजिटल सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
(B) खाद्य सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
(C) स्वास्थ्य देखभाल और शक्ति हेतु बुनियादी अवसंरचना
(D) दूरसंचार और परिवहन बुनियादी अवसंरचना

उत्तर: (A)

प्रश्नोत्तर

Q. अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना में नविश आवश्यक है। ” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा करें। (वर्ष 2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/spotlighting-infrastructure-investments>

